



सूचना का  
अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

—00—

क्रमांक एफ 1-1/2011/ 1-सूअप्र  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2015

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग.बिलासपुर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त कलेक्टर,  
छत्तीसगढ़।

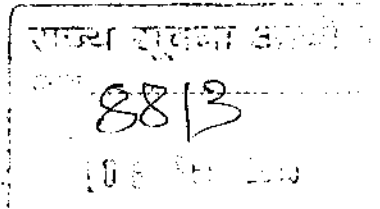
- विषय:- भारत सरकार से प्राप्त पत्र पर कार्यवाही बाबत- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत स्वप्रेरणा प्रकटीकरण का क्रियान्वयन बाबत।
- सन्दर्भ :- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नॉर्थ ब्लॉक, 32 नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन- No. 1/34/2013-IR दिनांक 29 जून 2015

—0—

विषयान्तर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन- No. 1/34/2013-IR दिनांक 29 जून 2015 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

2. निर्देशानुसार अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत स्वप्रेरणा प्रकटीकरण का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु की गई अनुशंसाओं का पालन सुनिश्चित करावें तथा पालन प्रतिवेदन से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (02)



(एन.एम. घोड़की)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 1-1/2011/ 1-13

नया रायपुर, दिनांक अगस्त 2015

प्रतिलिपि- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

- श्री संदीप जैन, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली की ओर उनके ज्ञापन F. No. 1/32/2013-IR दिनांक 17 फरवरी 2015 के तारतम्य में।
- राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़।
- प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
- रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- संचालक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर।
- सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, पुराना मंत्रालय (डीकेएस भवन) के पास, इन्द्रावती खण्ड, प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर, छ0ग0।
- राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग(RTI) की वेबसाईट में अपलोड करने बाबत।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

संस्कृत/प्रशासकीय विभाग  
(सूचना अधिनियम प्रकोष्ठ)  
पंजी. क्रमांक: 10/107/115  
दिनांक: 29/06/15

578/10/54708  
O/O CHIEF SECRETARY  
Govt. of Chhattisgarh  
Corr No. 60023/60I  
Date 29 JUN 2015

No.1/34/2013-IR  
Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions  
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi-1  
Dated: 29<sup>th</sup> June 2015

Office Memorandum

Subject: Implementation of Suo Motu Disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005

Attention is invited to detailed guidelines on implementation of suo motu disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005 issued vide this department's O.M. No.1/6/2011-IR dated 15.4.2013. Subsequently, a Committee of experts consisting of Shri A.N.Tiwari, Chief Information Commissioner(Retd) and Dr. M.M.Ansari, Information Commissioner(Retd) (of Central Information Commission) was constituted to recommend, interalia, measures to further strengthen implementation of Section 4 of the RTI Act, 2005. The Committee has, interalia, made the following recommendations which have been duly accepted by the competent authority:-

- 1) All the details of the public authority may be uploaded on its website. Access to information should be made user-friendly for which appropriate information technology infrastructure should be suitably designed, developed and operationalised.
- 2) All the training modules for professional upgradation of employees should incorporate matter relating to the virtues of transparency and open government and RTI law.
- 3) In order to minimise the burden of servicing RTI applications, the public authorities with high public dealings should put in place an effective system to redress the grievances of affected persons. At the sub-organisational levels, there should be cooperation and coordination between the Central Public Information Officers and the officers responsible for addressing public grievances.
- 4) In order to reduce the number of RTI applications relating to service matters, the information relating to recruitment, promotion and transfers should be brought into public domain promptly.
- 5) The retention and maintenance of specific documents for specified duration should be clearly spelt by each public authority in respect of its documents.

23 JUL 2015

64607

24 JUN 15

2. All the public authorities are requested to follow the above recommendations.

(1)

*Sandeep Jain*

(Sandeep Jain)

Director

Tel: 23092755

- 1) All Ministries/Departments of Govt of India
- 2) Union Public Service Commission /Lok Sabha Secretariat / Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ NITI Ayog/ Election Commission.
- 3) Central Information Commission/ State Information Commissions.
- 4) Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi.
- 5) The Comptroller and Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
- 6) Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie-248179, Uttarakhand
- 7) Director, Institute of Secretariat Training and Management, Old JNU Campus, Olof Palme Marg, New Delhi

Copy to :

Chief Secrefaries/ All State Governments